वैश्वीकरण की ओर बढ़ते लोग : भारत का आवक विप्रेषण*

वर्ष 2016-17 में भारत में आने वाले विप्रेषणों पर प्राधिकृत व्यापारियों के सर्वेक्षण के चौथे दौर का चित्रण करते हुए इस आलेख में यह पाया गया है कि विभिन्न एक्सचेंज हाउसों के साथ बिज़नेस टाइ-अप ने अन्य देशों की तुलना में गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल देशों से विप्रेषणों के सस्ते पारेषण की सुविधा दी है। इसके प्रमुख प्राप्तकर्ता राज्य केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। नकद –आधारित कम मूल्य के लेनदेनों के लिए मुद्रा अंतरण परिचालक (एमटीओ) बैंकों से ज्यादा बेहतर हैं।

प्रस्तावना

विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में कल्याण संबंधी पहलुओं के कारण विप्रेषण एक बड़े वर्ग के जीवन और आचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2017 में निम्न और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं ने विप्रेषण के रूप में यूएस$466 बिलियन प्राप्त किए (विश्व बैंक, 2018)। ये प्रवाह कतिपय निम्न आय अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी के आधे से ज्यादा भाग का निर्माण करते हैं। चक्रीय निजी ऋण और इक्विटी प्रवाहों की तुलना में विप्रेषण बाह्य वित्तपोषण का ज्यादा स्थिर स्रोत है, जिसमें इन दोनों के विपरीत चुकौती या संविदागत या अन्य ब्याज आदि के भुगतान का दायित्व नहीं होता है। बाह्य संधारणीयता दृष्टिकोण से इन प्रवाहों की यह विशेषता महत्वपूर्ण है।

विप्रेषण स्रोत अर्थव्यवस्थाओं में समष्टि आर्थिक परिस्थितियों, प्रवासियों का स्टॉक, मेजबान देशों में राजस्व नीति का रुझान, तेल कीमतें गतिकी और कार्य के लिए प्रवास संबंधी शासन पद्धति सहित अनेक प्रकार के कारकों पर निर्भर करते हैं (आरबीआई, 2015-16)। दिलचस्प बात ये है कि विप्रेषणों की लागत विप्रषणों के आकार को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक बन रहा है (सेचेट्टी एंड शोनेहोल्ट्ज़, 2018)। चूंकि विनियामक अपेक्षाओं के कारण औपचारिक माध्यम महंगे हैं, इसलिए विप्रेषक कम महंगे अनौपचारिक माध्यमों को तरजीह देते हैं, हालांकि वे कम सुरक्षित हैं, और उनका अवैध प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग हो सकता है (कोस्से एंड वेमेउलेन, 2014)। जी20 ने अपने एजेंडा में विप्रेषण की लागतों को प्राथमिकता दी है, और यह देश के स्तर पर उचित नीतियों को प्रोत्साहन दे रहा है।

भारत में आने वाले विप्रेषण व्यापार घाटे के वित्तपोषण के लिए महत्वपूर्ण रहा है (2017-18 में 43 प्रतिशत)। वर्ष 2017 में विश्व भर में फैले कुशल, अर्ध-कुशल और अकुशल भारतीय प्रवासियों के बड़े समूह द्वारा भेजे गए $69 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विप्रेषणों के साथ भारत शीर्ष प्राप्तकर्ता देश बना रहा।[2] अतएव, भारत में भेजे जाने वाले विप्रेषणों की लागत अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषत: अनौपचारिक/ अवैध माध्यमों के उपयोग की संभावना के दृष्टिकोण से।

वर्ष 2006 से भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) उन प्राधिकृत व्यापारियों का सर्वेक्षण करता आया है जो निवासियों द्वारा प्राप्त विप्रेषणों के लिए मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं। यह सर्वेक्षण, जो अपनी श्रृंखला में चौथा है[3], में पहली बार विप्रेषण भेजने की लागतों के साथ ही उनके देश-वार/ राज्यवार वितरण संबंधी सूचना को प्राप्त करने हेतु इसका दायरा बढ़ाया गया है।

यह लेख इस सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के इन नए आयामों से अभिप्रेरित है, जो स्रोत, गंतव्य, आकार, अंतरण के साधनों और विप्रेषणों की लागत के अनुसार आवक विप्रेषणों के बारे में गहनता से समझना चाहता है। लेख के शेष भाग को पाँच भागों में बांटा गया है (प्रस्तावना वाले भाग सहित)। भाग 2 में सर्वेक्षण का दायरा और प्रयुक्त पद्धति पर संक्षेप में चर्चा की गई है। भाग 3 में इस लेख के लक्ष्य के अंतर्गत पहले ही बताई गई विशेषताओं के अनुसार सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं। भाग 4 में

* यह लेख भारतीय रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रभाग, आर्थिक नीति और अनुसंधान विभाग के श्री राजन गोयल, परामर्शदाता, आविनीवि के मार्गदर्शन में श्री राजीव जैन, श्री धीरेन्द्र गजभिये तथा सुश्री सौमाश्री तिवारी द्वारा तैयार किया गया है। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं, तथा ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते ।

[1] सर्वेक्षण के प्राथमिक निष्कर्ष 09 अगस्त 2018 को आरबीआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए।

[2] कुल अंतरराष्ट्रीय स्टॉक में भारत का हिस्सा लगभग 6 प्रतिशत (16.4 मिलियन) है।

[3] इससे पहले के सर्वेक्षण जुलाई 2006, सितंबर 2009 और अप्रैल 2013 में किए गए।

विप्रेषण की लागतों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। भाग 5 में प्राप्त निष्कर्ष बताए गए हैं, जिनका उद्देश्य नीतिगत विकल्पों की जानकारी देना है।

2. सर्वेक्षण का कार्य-क्षेत्र एवं कार्य-प्रणाली

वैश्विक रूप से, विप्रेषण बाजार में वाणिज्यिक बैंक, मुद्रा अंतरण परिचालक (एमटीओ), एक्सचेंज हाउसों और डाक घरों के साथ ही एजेंट और सब-एजेंट के रूप में कार्य करने वाली अनेक प्रकार की वाणिज्यिक संस्थाएं कार्य करती हैं (बॉक्स 1)। भारत में आने वाले विप्रेषण प्रवाहों की मध्यस्थता में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सर्वेक्षण के इस दौर में आरबीआई को विदेशी मुद्रा लेनदेन रिपोर्ट करने वाले समस्त 80 एडी में से 42 एडी से प्रतिसाद प्राप्त किए गए, जिनकी वर्ष 2016-17 में रिपोर्ट किए गए कुल विप्रेषणों में 98.3 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। तीन प्रमुख एमटीओ, जिनके भारत में बड़े विप्रेषण परिचालन हैं, के बीच एक अलग प्रश्नावली परिचालित की गई।[4]

3. सर्वेक्षण के परिणाम

विभिन्न बैंकों के बीच विप्रेषण कारोबार काफी भिन्न रहा है। मध्यस्थों के कारोबारी मॉडलों में अंतर है, जो स्रोत देश, अंतरण के प्रचलित साधन और विप्रेषणों के आकार पर निर्भर करते हैं।

3.1 देश-वार विप्रेषण

भारत में प्राप्त विप्रेषणों का 82 प्रतिशत सात देशों से आरंभ होता है, नामत: संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस), सऊदी अरब, कतर, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम (यूके) और ओमान (चार्ट 1)। चूंकि विदेश में काम करने वाले भारतीयों में से 90 प्रतिशत गल्फ क्षेत्र और दक्षिण-पूर्व एशिया में हैं (आईएलओ, 2018) – जो अधिकतर अर्ध-कुशल और अकुशल मजदूर हैं – इसलिए इन देशों में तेल की कीमतों में तीव्र गिरावट और कठोर राजस्व स्थितियों के बावजूद वर्ष 2016-17 में कुल प्राप्त विप्रेषणों में गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) देशों का हिस्सा 50 प्रतिशत से अधिक

बॉक्स I: विप्रेषण चैनलों की सूक्ष्म संरचना

विप्रेषण लेनदेनों में हमेशा एक प्रेषक, एक प्राप्तकर्ता, दोनों देशों में मध्यस्थ और उनके द्वारा प्रयुक्त भुगतान इंटरफेस शामिल होते हैं। व्यवहार में, विप्रेषण औपचारिक और अनौपचारिक, दोनों चैनलों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। भिन्नतापूर्ण विनियामकीय व्यवस्था के कारण एक विशिष्ट चैनल किसी एक देश में औपचारिक हो सकता है, और दूसरे में अनौपचारिक (आकृति 1)।

आकृति 1: विप्रेषण चैनलों का विस्तृत ढांचा

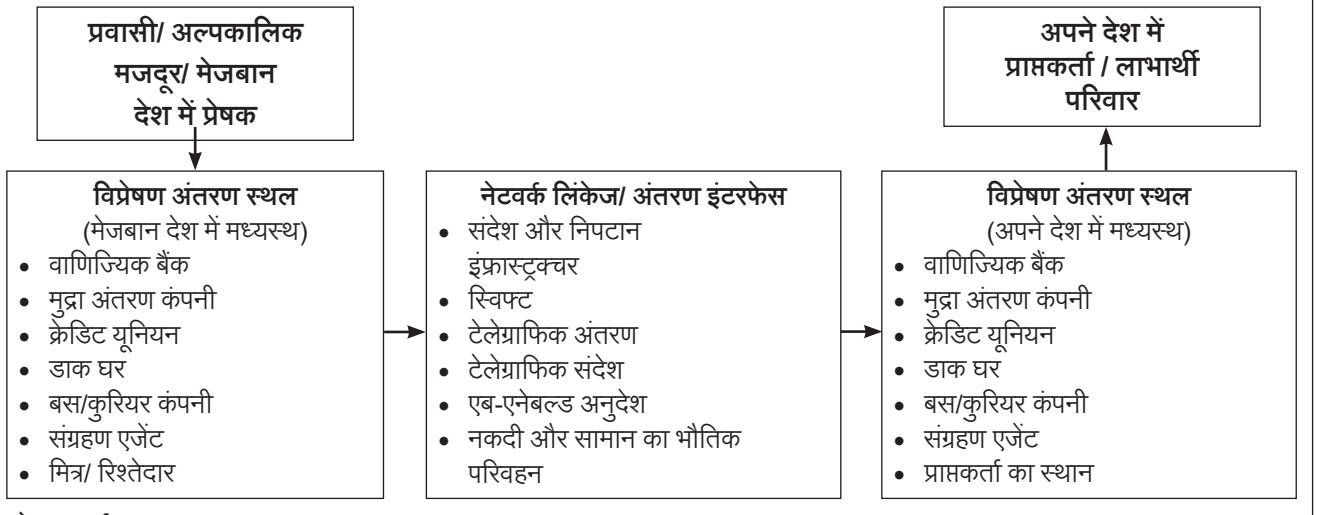

स्रोत : आईएमएफ, 2009।

[4] पिछले सर्वेक्षणों में एडी बैंक शाखाओं के प्रदर्श शामिल किए गए थे: एमटीओ शामिल नहीं किए गए थे।

चार्ट 1: विप्रेषणों का देश-वार वितरण

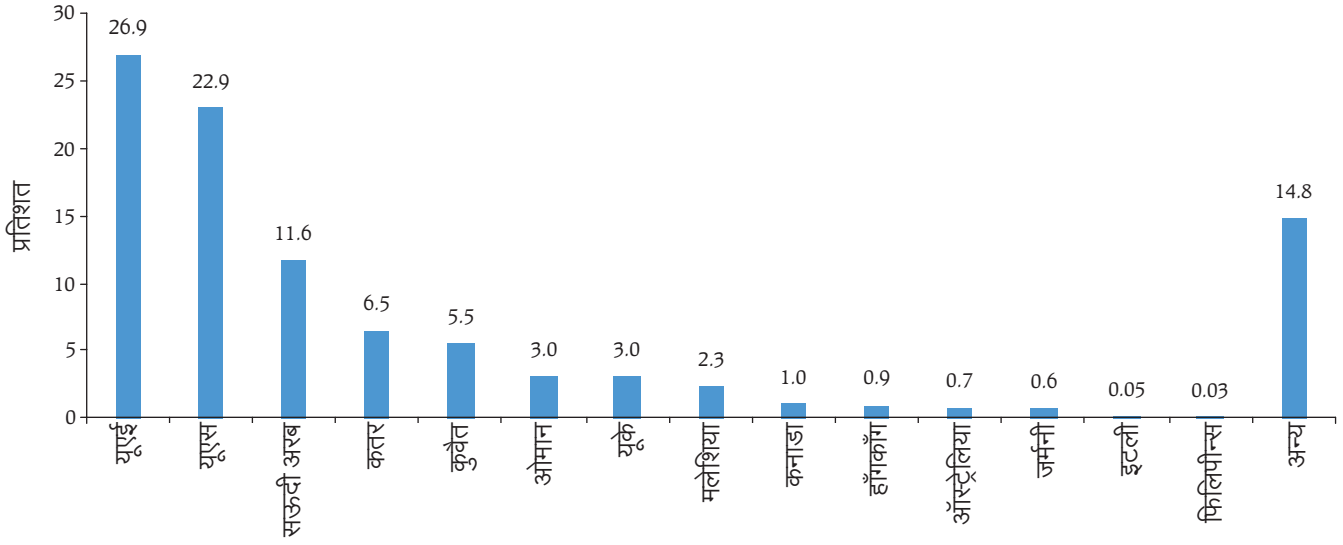

स्रोत : सर्वेक्षण आधारित अनुमान

था। दूसरा सबसे बड़ा योगदान यूएस में अधिक कुशलता और ऊंची कमाई की विशेषता वाले भारतीय प्रवासियों का है।

3.2 राज्य-वार विप्रेषण

सर्वेक्षण से पता चलता है कि कुल विप्रेषणों का 58.7 प्रतिशत हिस्सा चार राज्यों, नामत: केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ने प्राप्त किया। विप्रेषणों के प्रवाहों से मोटे तौर पर विदेश में प्रवासियों की राज्य-वार संरचना परिलक्षित होती है। कुल विप्रेषणों में 46 प्रतिशत हिस्से के साथ संयुक्त रूप से दक्षिणी राज्यों का दबदबा रहा है। इन परिणामों की बहुविध एजेंसियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए गए सर्वेक्षणों के द्वारा पुष्टि की गई है (उदा., आईएलओ, 2018), जिन्होंने सीमा-पार प्रवास के समृद्ध राज्यों, जैसे केरल और कर्नाटक से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से मुख्यत: आय के निम्न स्तर वाले निम्न या अर्ध-कुशल संविदा मजदूरों की ओर परिवर्तन को रेखांकित किया है। वर्ष 2016- 17 में कुल विप्रेषणों में इन दो राज्यों का हिस्सा 4.4 प्रतिशत रहा (सारणी 1)।

3.3 विप्रेषणों का साधन, आकार और प्रयोजन

एडी बैंक भुगतान अंतरणों की विभिन्न स्कीमों के माध्यम से परिचालन करते हैं, जिनका दायरा चेक, ड्राफ्ट जैसे पारंपरिक तरीकों से लेकर ऑन-लाइन सीधे अंतरण (अर्थात्

सारणी 1: आवक विप्रेषणों में राज्य-वार हिस्सा

प्रतिशत

राज्य	कुल विप्रेषणों में हिस्सा
केरल	19.0
महाराष्ट्र	16.7
कर्नाटक	15.0
तमिलनाडु	8.0
दिल्ली	5.9
आंध्र प्रदेश	4.0
उत्तर प्रदेश	3.1
पश्चिम बंगाल	2.7
गुजरात	2.1
पंजाब	1.7
बिहार	1.3
राजस्थान	1.2
गोआ	0.8
हरियाणा	0.8
मध्य प्रदेश	0.4
उड़ीसा	0.4
झारखंड	0.3
उत्तराखंड	0.2
पुदुचेरी	0.2
चंडीगढ़	0.2
जम्मू और कश्मीर	0.2
असम	0.1
हिमाचल प्रदेश	0.1
छत्तीसगढ़	0.1
अन्य	15.5
कुल	100.0

टिप्पणी: "अन्य" में ऐसे विप्रेषण भी शामिल हैं, जिनके लिए बैंक विनिर्दिष्ट गंतव्य की पहचान नहीं कर सके, और इसलिए ऐसे लेनदेन "अन्य" के अंतर्गत दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2: विप्रेषणों के साधन
(कुल विप्रेषणों में लिखत-वार हिस्सा)

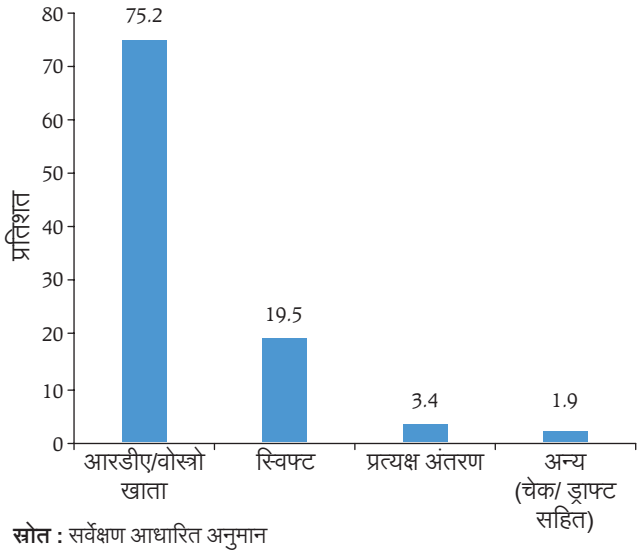

स्रोत : सर्वेक्षण आधारित अनुमान

चार्ट 3: विप्रेषणों का औसत आकार
(कुल विप्रेषणों में बकेट-वार हिस्सा)

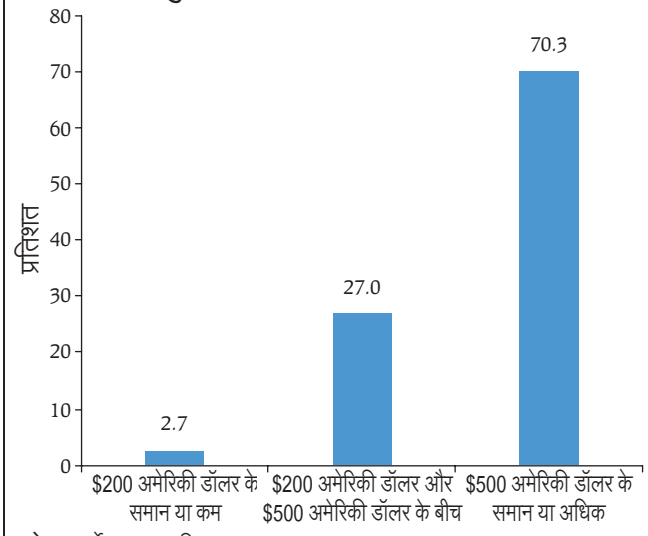

स्रोत : सर्वेक्षण आधारित अनुमान

वायर अंतरण), विश्वव्यापी वित्तीय दूरसंचार सोसायटी (स्विफ्ट) अंतरण, रुपया आहरण व्यवस्था (आरडीए) जैसे अधिक उन्नत, सरल और तेज गति वाले पारेषण चैनलों तक फैला है। सर्वेक्षण के परिणाम यह दर्शाते हैं कि विप्रेषणों का सबसे पसंदीदा साधन आरडीए है, विशेषत: जीसीसी देशों से, जो कुल विप्रेषणों का 75.2 प्रतिशत हिस्सा है। आरडीए उनके वोस्त्रो खाते खोलने और रखरखाव करने के लिए एडी-I बैंकों और अनिवासी एक्सचेंज हाउसों को जोड़ता (टाइ-अप) है। अनिवासी एक्सचेंज हाउस के रुपया/ विदेशी मुद्रा वोस्त्रो खाते में चेक/ ड्राफ्ट जमा होने के बाद बैंक तत्काल अंतिम प्राप्तकर्ता को विप्रेषण संवितरित करते हैं। प्रति बैंक ऐसे अधिकतम 20 टाइ-अप की अनुमति है।[5] इस चैनल के माध्यम से लेनदेनों की लागत अन्य चैनलों से कम है। दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सविफ्ट है, उसके बाद सीधे अंतरण और चेक और ड्राफ्ट आते हैं (चार्ट 2)। आकार-वार विश्लेषण यह दर्शाता है कि सभी रिपोर्ट किए गए लेनदेनों का 70.3 प्रतिशत $500 अमेरिकी डॉलर के बराबर या उससे अधिक के और केवल 2.7 प्रतिशत लेनदेन यूएस$200 के बराबर या उससे कम राशि श्रेणी के थे (चार्ट 3)।

बैंकों से प्राप्त प्रतिसादों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि भारतीय निवासियों द्वारा प्राप्त किए गए विप्रेषणों में से आधे से ज्यादा का उपयोग परिवार के रखरखाव (*अर्थात्* उपभोग) के लिए, उसके बाद बैंकों में जमाराशियों (20 प्रतिशत) और भू-संपदा और शयरों में निवेश (8.3 प्रतिशत) के लिए किया गया।

चार्ट 4: विप्रेषणों का प्रयोजन-वार वितरण

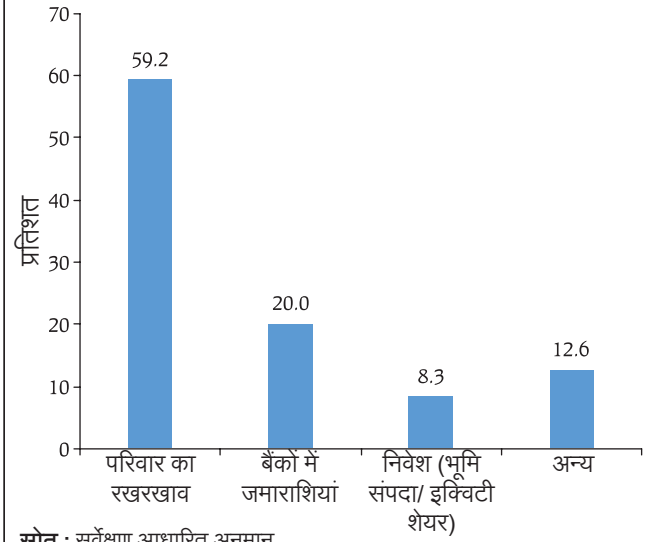

स्रोत : सर्वेक्षण आधारित अनुमान

[5] तथापि, आरबीआई के विनियमों के अनुसार जब आरडीए की कुल संख्या 20 पर पहुंच जाती है, एडी श्रेणी-I बैंक (आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार सभी चालू खाता और पूंजी खाता को शामिल करते हुए विदेशी मुद्रा में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक, राज्य सहकारी बैंक और शहरी सहकारी बैंक) अपनी आंतरिक प्रणाली की विस्तृत बाह्य लेखा-परीक्षा करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं, और ऐसी अधिक व्यवस्थाओं को प्राधिकृत किया जा सके।

4. विप्रेषणों की लागत

सीमा-पार विप्रेषण लेनदेनों में प्रेषक और प्राप्तकर्ता, दोनों के द्वारा लागत अपरिहार्य है, और वे इन लागतों के प्रति संवेदनशील होते हैं (गिब्सन और अन्य)। विश्व बैंक, और विशेषत: जी20 इन लागतों को कम करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यद्यपि वैश्विक विप्रेषणों के एक बड़े भाग की सुपुर्दगी अंतर्संबद्ध बैंकों और मुद्रा अंतरण परिचालकों (एमटीओ) द्वारा की जाती है, किंतु धन-शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) करने संबंधी विनियमों के कारण विभिन्न क्षेत्राधिकारों में यह नेटवर्क सिमट रहा है। वास्तव में, बर्कलेज, वेल्स फार्गो और बैंक ऑफ अमेरिका जैसे बहुराष्ट्रीय बैंकों ने अपना विप्रेषण कारोबार कम कर दिया है और एमटीओ द्वारा धारित खातों को भी बंद कर दिया है। वैश्विक रूप से, बैंकों की अत्यधिक नियत लागतों और अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं के कारण वे निधियां विप्रेषित करने के लिए खुदरा ग्राहकों का पसंदीदा विकल्प नहीं हैं (चंद्रमौलि, 2012)। वैश्विक रूप से, वर्ष 2018 की पहली तिमाही में $200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत 7.1 प्रतिशत थी, जो 2030 तक संधारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) के 3 प्रतिशत के लक्ष्य के दोगुने से भी ज्यादा है (विश्व बैंक, 2018)।

विप्रेषण भेजने की लागत अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है – गंतव्य; अंतरण का तरीका; भुगतान इन्फ्रास्ट्रक्चर; विप्रेषण का आकार, बाजार प्रतिस्पर्धा का फैलाव; तथा स्रोत और गंतव्य, दोनों देशों में प्रचलित विनियम। इसके अतिरिक्त, विनिमय दर मार्जिन, सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रभारित नियत शुल्क, ओरिजिनेटिंग मोड (ऑनलाइन या शाखा), लिखत के प्रकार और संबंधित मध्यस्थों (उदा. संपर्ककर्ता बैंक और लाभार्थी बैंक) के बीच राजस्व के बंटवारे की व्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न कॉरिडोर के बीच विप्रेषण की लागत भिन्न भिन्न पाई गई है।

4.1 प्रेषकों के लिए विप्रेषण लागत

सामान्यत: प्रेषक ही विप्रेषण की प्रत्यक्ष लागत वहन करता है। इसे सीमापार एजेंट – बैंक अथवा एक्सचेंज हाउस को अदा किया जाता है। सर्वेक्षण के परिणाम बताते हैं कि भारत में आने वाले कुल विप्रेषणों में से लगभग तीन चौथाई भाग को निजी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से भेजा जाता है (चार्ट 5)। इसके अलावा, एक बड़े भाग को आरडीए का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से निजी और विदेशी बैंकों द्वारा, भेजा जाता है (चार्ट 6)।

चार्ट 5: विप्रेषणों में बैंक-वार हिस्सा

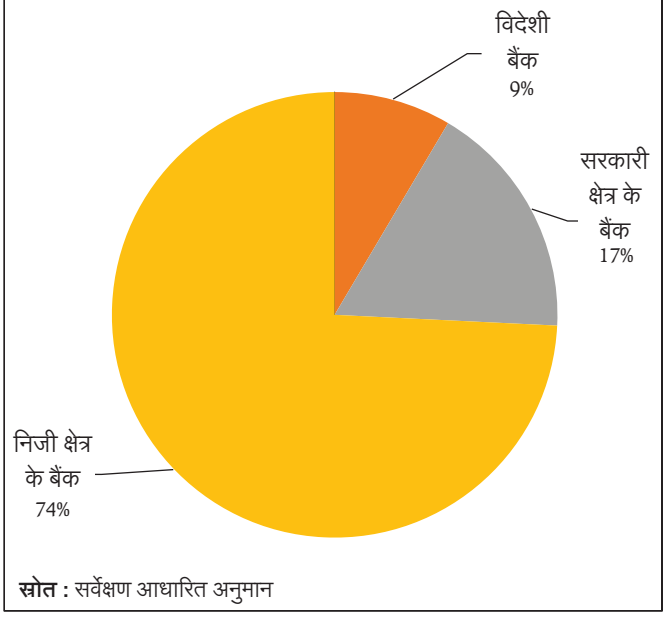

स्रोत : सर्वेक्षण आधारित अनुमान

आरडीए – सबसे महत्वपूर्ण माध्यम – सरकारी बैंकों की तुलना में विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए कम महंगा है (सारणी 2)।

सर्वेक्षण के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि भारत में विप्रेषण भेजने की लागत स्रोत/ वोस्त्रो लेनदेनों के द्वारा एक्सचेंज हाउसों के साथ परिचालन करते हैं, जिसकी लागत 2 से 4 प्रतिशत के

चार्ट 6: विप्रेषणों में साधन-वार हिस्सा

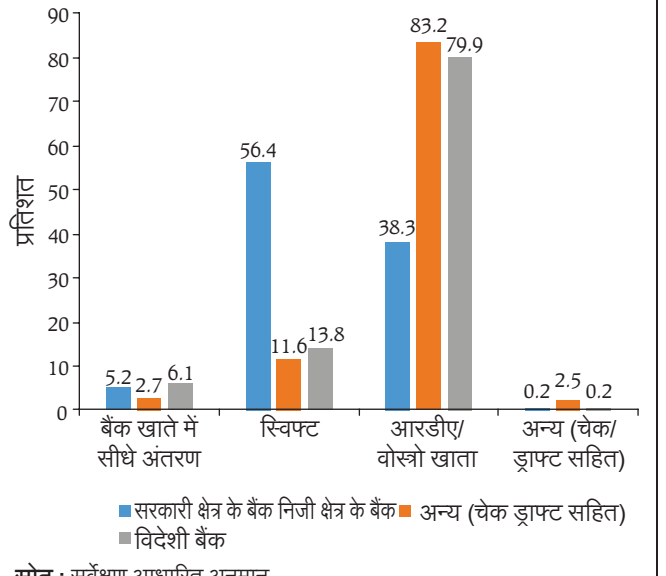

स्रोत : सर्वेक्षण आधारित अनुमान

सारणी 2: भारत को 200 अमेरिकी डॉलर एवं 500 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत[6]

प्रतिशत

	200 अमेरिकी डॉलर			500 अमेरिकी डॉलर		
बैंक का प्रकार/मोड	**सरकारी बैंक**	**निजी बैंक**	**विदेशी बैंक**	**सरकारी बैंक**	**निजी बैंक**	**विदेशी बैंक**
सीधे बैंक खाते में अंतरण/इलेक्ट्रॉनिक वायर	0-6.7	0-4.0	0-2.1	0-5.5	0-1.7	0-3.1
स्विफ्ट	0-21.3	0-22.7	0-12.7	0-8.6	0-9.2	0-7.7
आरडीए/वोस्त्रो खाता	0-13.5	0-11.8	0-8.5	0-5.5	0-4.8	0-14.1

बीच होती है, जो गैर-जीसीसी देशों की तुलना में कम है (सारणी 3)।

सर्वेक्षण से निकाला जा सकने वाला एक अन्य निष्कर्ष यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की परिचालन लागत सभी देशों में, आमतौर पर तुलनात्मक रूप से स्थिर होती है, जो विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में किफायती होने में कमी लाता है । दूसरी तरफ, निजी क्षेत्र के बैंकों के लागत पैटर्न में सभी देशों में तथा अंतरण के मोड में अंतर होता है । विदेशी बैंक न्यूनतम लागत में कार्य करते हैं, किंतु भारत में मुद्रा के प्रेषण में उनकी भूमिका सीमित है । करों की निर्धारित लागत के अलावा, इन बैंकों के विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन प्रभारों एवं कमीशन की व्यवस्था के चलते बैंकों के बीच लागत में अंतर होता है ।

हाल के वर्षों में हुई प्रौद्योगिकीय उन्नति के बावजूद यह पाया गया कि विप्रेषणों की समग्र लागत काफी अधिक बनी हुई है (मेला *एवं अन्य, 2017; सेक्केट्टी एवं स्कोएदहोल्ट्ज 2018, विश्व बैंक 2018) ।* भारत के मामले में, विभिन्न माध्यमों से विप्रेषण की साधारण औसत लागत 5 प्रतिशत के लक्षित स्तर से अधिक बनी हुई है (विश्व बैंक) । हालांकि, भारित औसत के आधार पर भारत में आने वाले विप्रेषणों की लागत जी20 द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तुलनीय प्रतीत होती है ।

सारणी 3: प्रेषणकर्ता द्वारा वहन की गई अधिकतम लागत : क्षेत्र-वार

	200 अमेरिकी डॉलर		500 अमेरिकी डॉलर	
लिखत	**गल्फ के देश**	**गल्फ से इतर देश**	**गल्फ के देश**	**गल्फ से इतर देश**
आरडीए/ वोस्त्रो खाता	4.4	13.5	1.9	5.5

टिप्पणी: प्राप्तकर्ता शीर्ष 10 बैंकों से प्राप्त सूचना पर आधारित ।

[6] सर्वेक्षण के तहत विप्रेषण भेजने की रिपोर्ट की गई लागत में विभिन्न बैंकों में काफी अंतर है, इसलिए इसे दायरे के रूप में दर्शाया गया है ।

4.2 विप्रेषणों की लागत का आकलन

विश्व बैंक के तत्वाधान में रिमिटेंसेज प्राइस वर्ल्डवाइड (आरपीडब्लू) सभी 365 "कंट्री कॉरिडोर्स" [7] में विप्रेषण भेजने की लागत की निगरानी करता है । आरपीडब्लू प्रमुख कोरिडोर्स[8] से संबंधित विप्रेषण भेजने की लागत के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए 200 अमेरिकी डॉलर (या समतुल्य) बेंचमार्क आकार का प्रयोग करता है ।

- भारत में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत 2013 के 9.1 प्रतिशत से घटकर 2018 की पहली तिमाही में 5.6 प्रतिशत रह गई (500 अमेरिकी डॉलर भेजने के संबंध में 4.9 प्रतिशत से घटकर 3.3 प्रतिशत रह गई), हालांकि, देश के भारांक (*अर्थात,* प्रत्येक कॉरिडोर से भारत के अंतर्वाही विप्रेषणें के मूल्य) को गणना में शामिल किया जाए तो भारित औसत लागत और भी कम होगी (चार्ट 7 एवं 8)[9]।

[7] कॉरिडोरों में विप्रेषण भेजने वाले 48 देशों को और प्राप्त करने वाले 105 देशों को शामिल किया गया है । भारत से विप्रेषण भेजे जाने की लागत की जानकारी चार देशों (*नामत:*, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका) के बारे में उपलब्ध है, किंतु भारत में विप्रेषण भेजे जाने की लागत की जानकारी 20 देशों (*नामत:*, आस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कुवैत, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ओमान, कतर, साउदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, थाइलैंड, यूएई, यूके एवं यूएस) के बारे में उपलब्ध है ।

[8] 25 मई 2018 को विश्व बैंक के आरपीडब्लू के डाटा रलीज के अनुसार, भेजी गई राशि के रूप में विप्रेषण लागत में कमी के संबंध में वैश्विक लक्ष्यों को 200 अमेरिकी डॉलर (या समतुल्य स्थानीय मुद्रा) पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह विशिष्ट विप्रेषण लेनदेन को परिशुद्धतापूर्वक दर्शाता है । हाल के समय तक, आरपीडब्लू 200 अमेरिकी डॉलर की राशि पर ध्यान केंद्रित किए हुए था । हालांकि, 500 अमेरिकी डॉलर (या समतुल्य) से संबंधित आंकड़े भी एकत्र किए गए हैं, किंतु विश्व बैंक ने इस उच्चतर राशि के संबंध में प्रवृत्तियों के संक्षिप्त विश्लेषण को जारी करना दिसंबर 2017 से प्रारंभ किया ।

[9] विप्रेषण लागतों में कमी के संबंध में वैश्विक लक्ष्यों के बारे में हुए प्रगति के मापन के लिए आरपीडब्लू सूचकों का प्रयोग किया जाता है । जी8 (लाक्विला, 2010) एवं जी20 (कैन्नस, 2011 एवं ब्रिसकैन, 2014) ने वैश्विक औसत कुल लागत को 5 प्रतिशत तक घटाने का वचन दिया । 2016 में, जी20 ने लक्ष्य; अर्थात विप्रेषण की लागत को 3 प्रतिशत से कम करने और एसडीजी के रूप में 2030 तक लागत के 5 प्रतिशत से अधिक लागत वाले कॉरिडोरों के विप्रेषणों को समाप्त किए जाने, को शामिल करते हुए अपने कार्य को 2030 के एजेंडा के अनुरूप बनाया ।

चार्ट 7: 2018 की पहली तिमाही में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत

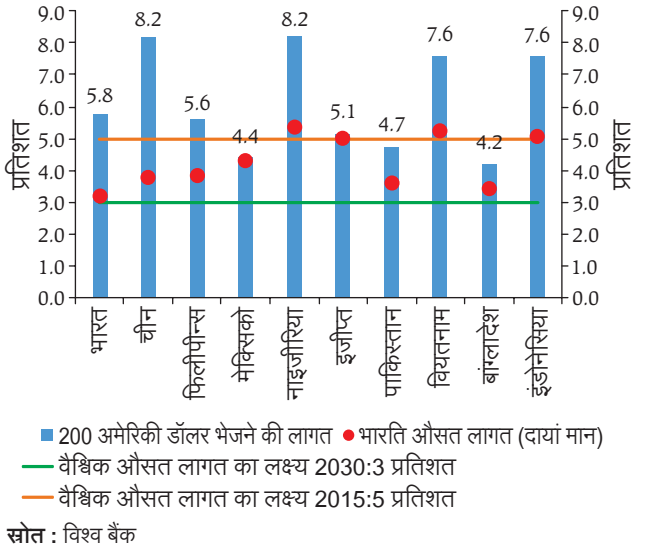

स्रोत : विश्व बैंक

चार्ट 8: 2018 की पहली तिमाही में 500 अमेरिकी डॉलर भेजने की औसत लागत

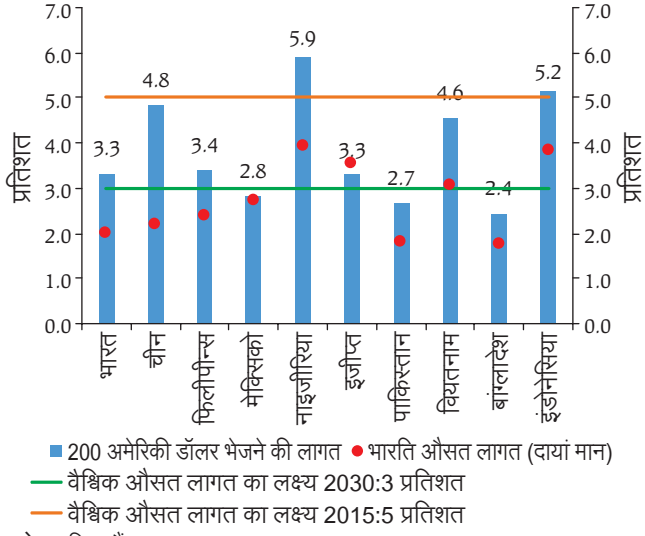

स्रोत : विश्व बैंक

- थाइलैंड और जापान के साथ का कॉरिडोर विशेषरूप से महंगा है, जिसमें मूलधन के 10 प्रतिशत से अधिक लागत लगती है । हालांकि, आने वाले कुल विप्रेषणों में इन देशों की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत थी (चार्ट 9) ।
- उच्च लागत वाले कॉरिडोरों (उदा. थाइलैंड और जापान) से विप्रेषण भेजने की लागत अन्य प्रमुख विप्रेषण कॉरिडोरों के मामलों में भी अपेक्षाकृत अधिक पाई गई, जो यह दर्शाता है कि इन देशों में विप्रेषणों से संबंधित वित्तीय सेवाएं महंगी हो सकती हैं (चार्ट 10) ।
- बैंकों और एमटीओ के माध्यम से भारत को 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत घट जाने (चार्ट 11) के बावजूद बैंकों के प्रभार एमटीओ द्वारा लगाए जाने वाले प्रभारों के लगभग दोगुने हैं, जो संभवत: एएमएल/सीएफटी विनियमनों के संबंध में अनुपालन की उच्चतर लागत को दर्शाता है ।

चार्ट 9: प्रमुख कॉरिडोर के संबंध में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत

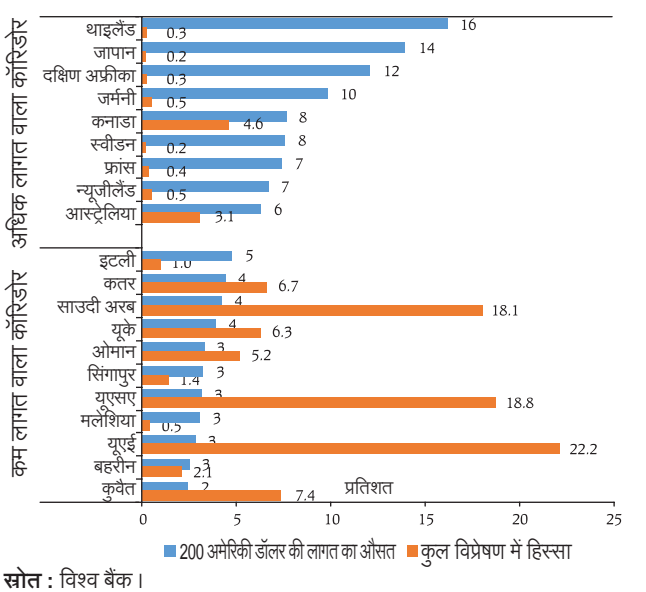

स्रोत : विश्व बैंक ।

चार्ट 10: भारत के उच्च लागत वाले कॉरिडोर से अन्य प्रमुख प्राप्तकर्ता देशों में 200 अमेरिकी डॉलर भेजने की लागत

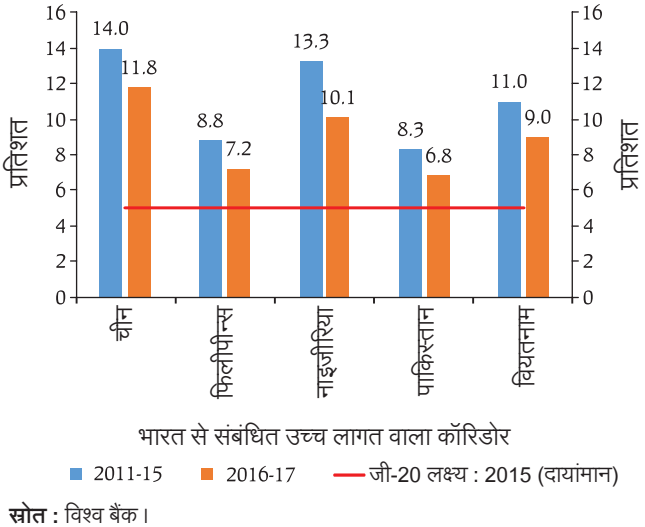

स्रोत : विश्व बैंक ।

चार्ट 11: बैंकों एवं एमटीओ द्वारा विप्रेषण भेजने की लागत

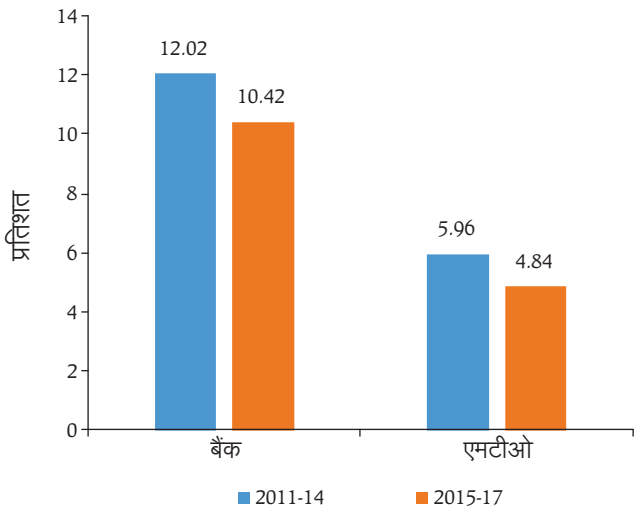

स्रोत : विश्व बैंक

4.3 प्राप्तकर्ताओं के लिए विप्रेषण की लागत

जैसा कि पहले जिक्र किया गया, विप्रेषण लेनदेन की लागत का कुछ हिस्सा प्राप्तकर्ता को वहन करना पड़ सकता है, जो कमीशन, कर या विदेशी मुद्रा प्रभार के रूप में हो सकता है, जिसका निर्धारण मध्यस्थों के बीच हुए करार की प्रकृति पर निर्भर होगी । सर्वेक्षण के परिणामों से प्राप्तकर्ताओं द्वारा वहन की जाने वाली लागत में बहुत अंतर होने का पता चलता है, जिसमें सभी स्रोत देशों और अंतरण के मोड में विभेदन भी शामिल हैं।

विभिन्न मोड (चेकों एवं ड्रॉफ्टों को छोड़कर) के माध्यम से 200 अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने की लागत में, सभी बैंकों में, विप्रेषित राशि के शून्य से 13.3 प्रतिशत तक परिवर्तन हुआ है । यह लागत सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी एवं विदेशी बैंकों की तुलना में कम रही । विशेषरूप से, निजी क्षेत्र के बैंकों के पास विप्रेषण कारोबार का बाजार में सबसे बड़ा हिस्सा होने के बावजूद वे शून्य से 12.6 प्रतिशत के दायरे में प्रभार लगाते हैं । 500 अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण के मामले में, सभी बैंकों में यह लागत आधी हो जाती है; हालांकि, यह बैंकों के लिए बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करता है । जीसीसी देशों के मामले में, एक्सचेंज हाउसों से समझौता वाले बैंकों के खाता-से-खाता लेनदेन हो रहे हैं । इसके कारण प्राप्त होने वाले विप्रेषणों की प्रभावी लागत शून्य हो जा रही है, सिर्फ कर वाले हिस्से की कटौती की जाती है ।

4.4 मुद्रा अंतरण के परिचालन

पूरी दुनिया के विप्रेषण क्षेत्र में गैर-बैंकिंग प्रतिभागियों के बीच, एमटीओ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं । एमटीओ वित्तीय कंपनियां होती हैं जो उनके ग्राहकों की तरफ से, या तो आंतरिक प्रणालियों का प्रयोग करते हुए या फिर अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क का प्रयोग करते हुए, निधियों का अंतरराष्ट्रीय अंतरण करने का कार्य करते हैं । भारत के मामले में भी, एमटीओ उन प्रवासी कामगारों की जरूरतों को पूरा करके महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, जो वित्तीय निरक्षरता सहित विभिन्न कारणों से बैंकिंग माध्यम का प्रयोग कर पाने में सक्षम नहीं हैं । प्रवासी भारतीयों को सेवाएं प्रदान करने वाले एमटीओ विप्रेषणों के अंतरण हेतु उनके स्वयं के आउटलेटों या अन्य अंतरण ऐजेंटों (*उदा.* बैंक, एक्सचेंज ब्यूरो, डाक घर, सेल फोन सेंटर, ट्रेवल ऐजेंसी, ड्रग स्टोर्स एवं गैस स्टेशन) के नेटवर्क का प्रयोग करते हैं । महत्वपूर्ण बात यह है कि एमटीओ के माध्यम से विप्रेषण की लागत बैंकों *की तुलना में* प्रतिस्पर्धी है और वे सामान्यत: कम मूल्य के नकदी लेनदेन के लिए लोकप्रिय हैं । वस्तुत:, फिनटेक में हुई हाल की तीव्र वृद्धि ने एमटीओ को विप्रेषण के कारोबार में बैंकिंग क्षेत्र के प्रभुत्व को चुनौती प्रस्तुत करने के लिए सक्षम बनाया (बॉक्स II) ।

सारणी 4: भारत में प्राप्तकर्ता द्वारा वहन की जाने वाली लागत

प्रतिशत

	200 अमेरिकी डॉलर			500 अमेरिकी डॉलर		
बैंक का प्रकार/मोड	सरकारी बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक	सरकारी बैंक	निजी बैंक	विदेशी बैंक
सीधे बैंक खाते में अंतरण/इलेक्ट्रॉनिक वायर	0-1.5	0-1.9	0-2.0	0-0.7	0-1.1	0-0.8
स्विफ्ट	0.5-4.4	0-12.7	0-13.3	0-2.5	0-6.3	0-5.4
आरडीए/वोस्त्रो खाता	0-2.4	0-4.5	0-5.5	0-1.0	0-1.8	0-2.0
अन्य (चेक एवं ड्रॉफ्ट सहित)	0-2.3	0-12.6	0-40.4	0-1.0	0-5.1	0-16.4

बॉक्स ।।: एमटीओ के परिचालगत एवं लागत संबंधी पहलू

एमटीओ मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के अधीन सीमा-पार निधि अंतरणों के विशेष विक्रय अधिकार आधारित नेटवर्क (फ्रेंचाइज्ड नेटवर्क) के माध्यम से परिचालन करते हैं। इसके अंतर्गत विदेश स्थित प्रतिष्ठित मुद्रा अंतरण कंपनियों, जिन्हें 'ओवरसीज प्रिंसिपल' के रूप में जाना जाता है और भारत में स्थित अभिकर्ताओं (ऐजेंट), जिन्हें 'इंडियन ऐजेंट्स' के रूप में जाना जाता है; के बीच गठबंधन होता है । इनमें से बाद वाले, अर्थात इंडियन ऐजेंट्स सीधे तौर पर या फिर उप-अभिकर्ताओं के माध्यम से अंतिम लाभार्थी के लिए आहरित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं (आरेख 1)। 'ओवरसीज प्रिंसिपल' को पंजीकृत संस्था होना चाहिए, जिसे मुद्रा अंतरण संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु मेजबान देश के वित्तीय विनियामकीय प्राधिकार द्वारा भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस एक्ट) 2007 के तहत भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग (भा.रि.बैं.) की अनुमति से अनुज्ञप्ति (लायसेंस) जारी की गई होना चाहिए । इंडियन ऐजेंट को एडी-। या एडी-।। बैंक अथवा संपूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी), कोई डाक घर होना चाहिए, जो उप-अभिकर्ता, *नामत:* खुदरा बिक्री केंद्र (रिटेल आउटलेट) एवं वाणिज्यिक संस्थानों को नियुक्त कर सकें।

एमटीओ के माध्यम से किए जाने वाले विप्रेषणों का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा जीसीसी देशों से होता है । सर्वेक्षण से पता चलता है कि एमटीओ के संबंध में भेजने की औसत लागत बैंकों की तुलना में कम है और विप्रेषणों के अपेक्षाकृत अधिक मूल्य के होने के साथ लागत का अंतर कम होता जाता है । एमटीओ के माध्यम से 200 अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण की लागत विप्रेषित की जाने वाली राशि का 0-11.1 प्रतिशत तक होता है, जो बैंकों द्वारा सभी क्षेत्रों (कॉरिडोर) में कुल विप्रेषित की जाने वाली राशि के 0-22.7 प्रतिशत होने की तुलना में काफी कम है । हालांकि, 500 अमेरिकी डॉलर भेजने के मामले

आरेख 1: एमटीओ के लिए निधि अंतरण-प्रक्रिया

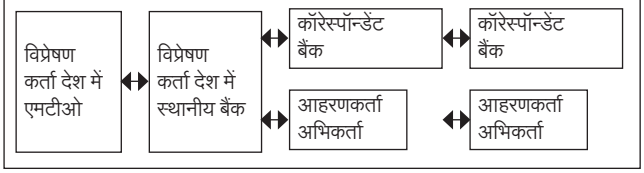

चार्ट ।।.1: विभिन्न बैंकों और एमटीओ में भेजने वाले की लागत

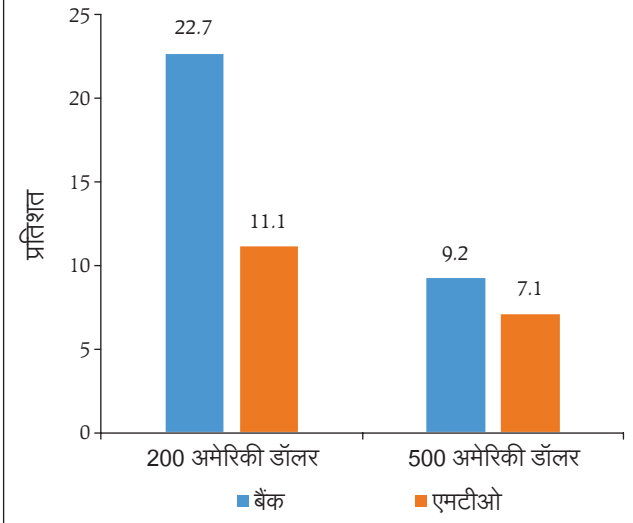

स्रोत : सर्वेक्षण आधारित अनुमान ।

में लागत का अंतर कम होता है, जो एमटीओ और बैंकों के संबंध में क्रमश: 7.1 प्रतिशत और 9.2 प्रतिशत होता है (चार्ट II.1) ।

एमटीओ *की तुलना में* बैंकों द्वारा विप्रेषण की लागत में अंतर सभी देशों और क्षेत्रों में विद्यमान है, जिसके अंतर्गत पहले वाले, अर्थात एमटीओ की उपरिलागत संरचना के अपेक्षाकृत कम रहने और समेकित अंतरणों के संबंध में बेहतर विनिमय दर होने के कारण उनके मूलभूत सामर्थ्य और किफायती होने में वृद्धि हुई । इसके अलावा, एमटीओ के मामले में, लागत संरचना तुलनात्मक रूप से अधिक परिवर्तनशील है और इस पर त्योहारों, स्थानों, विशेष मूल्यन और विपणन प्रोत्साहनों (मार्केटिंग प्रोमोशन) जैसे विभिन्न कारकों का असर पड़ता है । समग्ररूप से, इन लाभों के कारण पैसे भेजने वाले एमटीओ के प्रयोग या अधिक अनौपचारिक एवं जोखिमपूर्ण माध्यमों का प्रयोग करने की ओर प्रवृत्त होते हैं ।

भारत के मामले में, एमटीओ के माध्यम से होने वाले कुल लेनदेन में से 90 प्रतिशत से अधिक नकदी आधार पर किए जाते हैं (चार्ट II.2) । इन माध्यमों से बेनामी अंतरणों तथा उच्च मूल्य के लेनदेन के बहुत सारे कम मूल्य के लेनदेन में बंट जाने का जोखिम बढ़ सकता है । दूसरी ओर, बैंक बाधारहित और सुरक्षित विप्रेषण माध्यम उपलब्ध कराते हैं, जो सभी

(जारी...)

चार्ट ।।.2: बैंकों और एमटीओ के लिए विप्रेषणों के प्राथमिक माध्यम (मोड)

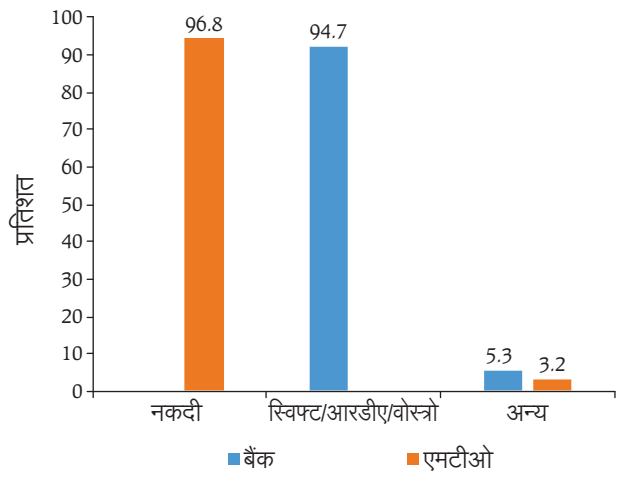

स्रोत : विश्व बैंक

विनियामकीय अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं, किंतु उनकी लागत अधिक होती है ।

संदर्भ

इंटरनेशनल रिमिटेंसेज, फिनैकल फ्रॉम इन्फोसिस, अक्तूबर 2011.

मुद्रा अंतरण सेवा योजना से संबंधित मास्टर परिपत्र, मास्टर परिपत्र सं. 1/2015-16, जुलाई 2015, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasterCirculars.aspx?Id=9895&Mode=0

मास्टर निर्देश – मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस), फरवरी 2017, एफईडी मास्टर निदेश सं. 1/2016-17, https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=10868&fn=5&Mode=0

5. निष्कर्ष

सारांश रूप में, सर्वेक्षण से विप्रेषणों के विभिन्न पहलुओं के बारे में कुछ रोचक जानकारी प्राप्त होती है, जिसका प्रयोग हितकारी नीतिगत पारिस्थितिक तंत्र विकसित और तैयार करने में किया जा सकता है। इस तंत्र का उपयोग सुव्यवस्थित ढंग से न्यूनतम लागत पर भारत में महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा को विकसित करने और उसमें वृद्धि करने के लिए किया जा सकता है, ताकि कल्याण संबंधी लाभ भेजने वालों, प्राप्तकर्ताओं और भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलें। सर्वाधिक आने वाला विप्रेषण केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक को प्राप्त होता है। यह ऐसी विशेषता है जिसका प्रयोग विप्रेषण प्रवाह के पसंदीदा स्थान के चुनाव के लिए किया जा सकता है और जिन राज्यों को अपेक्षाकृत कम विप्रेषण की प्राप्ति होती है उनके लिए यह अनुकरणीय है क्योंकि भारत की जनसंख्या का हिस्सा, जिसमें हमेशा वृद्धि हुई है; काम की तलाश में, जो उनके कौशल और जनांकिकी के अनुरूप हो, विदेशों में जाता है। जीसीसी देश विप्रेषण के प्रमुख स्रोत हैं और विभिन्न एक्सचेंज हाउसों के साथ कारोबारी समझौतों के कारण अन्य देशों से विप्रेषण की तुलना में कम लागत पर विप्रेषणों की सुविधा प्राप्त हुई। इन स्रोतों -जी2जी; बी2बी; एवं पी2पी,[10] की क्राउडिंग-इन, को पल्लवित करने हेतु इन्हें प्राथमिकता प्रदान करने की जरूरत है ताकि टिकेट साइज को बढ़ाया जा सके और लागत को कम किया जा सके । इसके अलावा, सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि बैंकों की आरडीए की बेहतर उपलब्धता होने के बावजूद एमटीओ द्वारा लगाई जाने वाली समग्र लागत काफी कम है। ऐसा होना कम मूल्य के विप्रेषण कारोबार और डायनेमिक कॉस्ट स्ट्रक्चर में उनके कोर लाभों के कारण होने की संभावना है । तदनुसार, एमटीओ तथा वे जिस नीतिगत ढांचे के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं उसे पुनर्समायोजित करने की जरूरत है ताकि वे बड़ी और संभावनापूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में कार्य कर सकें तथा उन्हें बैंकों *की तुलना में* समान परिस्थितियां मिल सकें। ऐसा किए जाने के लिए एएमएल/सीएफटी व्यवस्था की सावधानी पूर्वक समीक्षा किए जाने की जरूरत होगी, जो चातुर्यपूर्ण, पारदर्शी और प्रभावी हो किंतु छोटे परिचालनकर्ताओं और नेटवर्कों के लिए सहायक हो। ये नीतिगत उपाय किए जाने के क्रम में, भारत ने तुलनात्मक लाभ के रूप में शुरुआत की है। आरपीडब्लू से लिए गए कॉरिडोर-वार आंकड़े से पता चलता है कि भारत में विप्रेषण भेजने की भारित औसत लागत विश्व बैंक द्वारा निर्धारित साधारण औसत लागत, जिसका प्रयोग विप्रेषण लागतों में कमी लाने में हुई प्रगति की निगरानी करने के लिए की जाती है, की तुलना में कम है ।

[10] जी2जी : सरकार से सरकार को; बी2बी : कारोबार से कारोबार को; पी2पी : व्यक्ति से व्यक्ति को होने वाले लेनदेन।

संदर्भ :

सेसेट्टी, स्टीफन एवं किम स्कोन्होल्ट्ज (2018), "द स्टबॉर्नली हाई कॉस्ट ऑफ रिमिटेंसेज", https://voxeu.org/article/stubbornly-high-cost-remittances.

चंद्रमौली, आनंद (2012), "रिमीटेंस मार्केट : रेडी एंड वेटिंग फॉर इट्स 'स्काइप' मॉमेंट", *कॉग्निजेंट रिपोर्ट*, नवंबर.

गिब्सन, जे. एंड एच. रोहोरुआ (2006), "हाउ कॉस्ट इलास्टिक आर रिमिटेंसेज ? इविडेंस फ्रॉम टोंगन माइग्रेंट्स इन न्यूजीलैंड", पेसिफिक इकोनॉमिक बुलेटिन, खंड.21(1) : 112-128.

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2009), इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स इन रिमिटेंसेज : गाइड फॉर कंपाइलर्स एंड यूजर्स, सांख्यिकी विभाग, आईएमएफ, वाशिंगटन, डी.सी. ।

कॉस्से, अन्नेके एवं रॉबर्ट वेर्मेउलेन (2014), "माइग्रेंट्स चॉइस ऑफ रिमिटेंस चैनल : डू जनरल पेमेंट हैबिट्स प्ले ए रोल ?", ईसीबी वर्किंग पेपर सीरीज नं. 1683, जून ।

मेला, माउरो (2017), "क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंसेज प्राइसिंग – डज मार्केट स्ट्रक्चर ड्राइव द प्राइसेज फॉर क्रॉस-बॉर्डर रिमिटेंसेज इन साउथ अफ्रीका ?", फिनमार्क ट्रस्ट रिपोर्ट ।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2006), भारतीय रुपया (आईएनआर) के विप्रेषण की लागत से संबंधि कार्य दल की रिपोर्ट ।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2016), वार्षिक रिपोर्ट 2015-16.

दुनिया भर में विश्व बैंक के विप्रेषणों का डाटाबेस ।

विश्व बैंक (2018), माइग्रेशन एंड रिमिटेंसेज – रीसेंट डेवलपमेंट एंड आउटलुक, अप्रैल, 2018.